>

Title: Need to ensure timely payment of post matric scholarships to the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर): मैं आपके माध्यम से सामाजिक एंव अधिकारिता व जनजाति कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के छात्र, जिन्हें मैट्रिक छात्रवृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है, उनकी राशि समय पर स्वीकृत नहीं होने से, पर्याप्त प्रावधान नहीं होने से और राशि दिल्ली से जिला स्तर तक जाने में पूरा वर्ष निकल जाता है। इस वजह से छात्रों को समय पर छात्रवृति नहीं मिलती है जिससे छात्र आर्थिक रूप से परेशान होते हैं। राजस्थान राज्य में करीब 46 करोड़ 21 लाख रुपए गत वर्ष योजना का बाकी है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसे जारी किया जाए।